

सेहत के लिए सहयोग

महाराष्ट्र में जब फरवरी में बर्ड फ्लू के खिलाफ संघर्ष शुरू हुआ तो अमेरिकी दूतावास के मानव सेवा कार्यालय ने इस रोग की पहचान और इसके प्रकाप को फैलने से रोकने के लिए भारतीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ कंधे से कंधा मिला कर काम किया। रोग को महामारी बनने से रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। इस रोग की रोकथाम, नियंत्रण तथा उन्मूलन के लिए अमेरिका-भारत सहयोग का लक्ष्य भी यही है।

अमेरिकी दूतावास के स्वास्थ्य अताशे अल्टाफ ए. लाल कहते हैं, “दूतावास के स्वास्थ्य विभाग की विशेषज्ञ एजेंसी ‘सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसीपी)’ ने मानव नमूनों में बर्ड फ्लू के विषाणु (वायरस) की पहचान करने के लिए राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे तथा राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान को नैदानिक रिएंजेट प्रदान किए। इससे पता लगता है कि हमने कितनी जल्दी रिएंजेंटों की नई प्रौद्योगिकी भारत को दी और भारत ने कितनी तेजी से उसका उपयोग कर लिया।”

सीडीसीपी पक्षियों के इंस्टीट्यूट यानी बर्ड फ्लू का पता लगाने और उसकी पहचान में मदद करने के लिए भारतीय प्रयोगशालाओं तथा अन्य संस्थानों को लगातार तकनीकी सहयोग दे रहा है। दूतावास का स्वास्थ्य विभाग बर्ड फ्लू के टीके पर अनुसंधान तथा इसको फैलने से रोकने में सहयोग देने के लिए भारत में दो जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों की नियुक्ति करेगा। अमेरिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस रोग पर निगरानी की क्षमता को बढ़ाने तथा प्रयोगशाला में इसका पता लगाने के लिए

भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। महामारी को रोकने और इसका नियंत्रण करने में ये दोनों ही काम बहुत महत्वपूर्ण हैं।

दूतावास का स्वास्थ्य विभाग विगत चार दशकों से भारतीय विशेषज्ञों के साथ मिलकर चिकित्सा अनुसंधान, जन स्वास्थ्य और रोग के नियंत्रण, रोकथाम तथा उन्मूलन पर काम कर रहा है। रोग नियंत्रण केंद्रों के अंतरिक्षत खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफ.डी.ए.) सहित स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभाग की अन्य एजेंसियों ने भारतीय स्वास्थ्य संस्थानों तथा संगठनों के साथ संयुक्त गतिविधियों के लिए अपना कार्यक्षेत्र बढ़ा लिया है। रोटावायरस के लिए टीके का विकास इसी सहयोग का सुपरिणाम है। यह विषाणु भारत में बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार है।

भारत में पोलियो का उन्मूलन भी इस सहयोग की एक और सफलता कथा है। इसके लिए भारत सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ तथा अमेरिका के स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभाग ने एक टीम के रूप में काम किया और दस वर्ष पहले जहां पोलियो पीड़ितों की संख्या 40,000 थी, आज वह घट कर करीब 40 रह गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, नई दिल्ली में संचारी रोग निगरानी तथा प्रतिक्रिया के क्षेत्रीय सलाहकार सुभाष सुलांके कहते हैं, “सरकार इस रोग के उन्मूलन पर जोर दे रही है, इसलिए हम वैज्ञानिक नीति और मानक मार्गदर्शन पर सलाह देते हैं। रोग को दूर करने के लिए आवश्यक टीकाकरण सुनिश्चित किया जाता है।” पोलियो उन्मूलन के लिए भारत में चार रोग नियंत्रण केंद्रों में पूर्णकालिक विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। इसके अलावा, हर

माह एजेंसी के अटलांटा, जॉर्जिया स्थित मुख्यालय से भी दो-तीन तकनीकी सलाहकार यहां आते हैं।

हम पोलियो के पूर्ण उन्मूलन के बहुत कारीब पहुंच चुके हैं। बस, केवल उत्तर प्रदेश तथा बिहार के कुछ इलाकों में पोलियो के तकरीबन 40 मामलों की सूचना मिली है। लाल कहते हैं, “समुचित टीकाकरण कार्यक्रम और वैशिक समुदाय के सहयोग से पोलियो को देश में पूरी तरह नेस्तनाबूद किया जा सकता है।” अमेरिकी तथा भारतीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने पूर्वानुमान लगाया था कि भारत में 2004 के अंत तक पोलियो का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया जाएगा लेकिन इस समयसीमा तक यह संभव नहीं हुआ। जब तक पोलियो का कोई भी छिटपुट मामला आगर कहीं है तो उससे रोग का प्रकोप फिर फैल सकता है। इसीलिए भारत के कोने-कोने और पड़ोसी देशों में भी टीकाकरण जरूरी है।

सहयोग के उदाहरण

- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ भारत में 125 से भी अधिक अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सहायता राशि प्रदान कर रहा है जबकि 1990 तक ऐसी कोई सहायता उपलब्ध नहीं थी। इनमें एच आई वी/एइस, टी.बी., मलेरिया, रोटा वायरस तथा अन्य से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। भारत में स्वास्थ्य तथा मानव सेवा क्षेत्र के 6 परामर्शदाता प्रयोगशालाएं एच आई वी/एइस, इसकी रोकथाम तथा उपचार पर काम कर रहे हैं।
- स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभाग ने भारत में सात द्विपक्षीय कार्यक्रम शुरू किए हैं

जिनके अंतर्गत टीके के विकास, विज्ञ रिसर्च, रोग का पता लगाने, स्वास्थ्य के पर्यावरणीय तथा व्यावसायिक पहलू, एचआईवी/एड्स की रोकथाम तथा जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाया जा सकता है। दूतावास का स्वास्थ्य विभाग भारत में जन स्वास्थ्य संबंधी स्कूलों की स्थापना में भी मदद देता है। मार्च में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक ऐसे जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठान की नींव रखी जिसके द्वारा स्थापित स्कूलों के ग्रेजुएट रोग नियंत्रण तथा रोकथाम के कुशल विशेषज्ञ होंगे।

- चिकित्सा विज्ञान, जन स्वास्थ्य तथा प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण पर आयोजित कार्यगोष्टियों में भारतीय विशेषज्ञ मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, टीके के विकास तथा नैदानिक अनुसंधान की नवीनतम तकनीकों पर विचारों तथा सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं। इसके लिए सहायता राशि स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभाग से प्राप्त होती है। इस सहायता में भारतीय स्वास्थ्य जांचकर्ताओं को अमेरिकी विशेषज्ञों के साथ काम करने के लिए प्राप्त होने वाली अनुदान राशि भी सम्मिलित है।
- लाल कहते हैं, “हर साल करीब 400 अमेरिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञ भारत आते हैं और लगभग इतनी ही संख्या में भारतीय विशेषज्ञ अमेरिका प्रयोगशालाओं में जाते हैं।” वह कहते हैं, “वे चिकित्सा अनुसंधान के राजदूत हैं। वे रोग के बारे में मिलकर अनुसंधान करते हैं, वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करते हैं और रोग के नियंत्रण, रोकथाम तथा बचाव के तरीके भी खोजते हैं।”